

भारत सरकार
मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 424
दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: जानवरों पर गर्मी का प्रभाव

424. श्री पी.पी. चौधरी:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेजी से बढ़ते तापमान के कारण झुलसाती गर्मी से जानवरों को मृत्यु और रोगों से बचाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर
मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री
(डॉ० संजीव कुमार बालियान)

(क) जी, हां।

(ख) कृषि और इसके सहायक विषय नामतः पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन राज्य के विषय हैं। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने और तेजी से बढ़ते तापमान की वजह से झुलसाती गर्मी के कारण होने वाली मौतों और रोगों समेत विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए अधिकृत हैं।

जहां तक पशुपालन और डेयरी विभाग का संबंध है, विभाग ने 2016 में आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, लू इत्यादि के दौरान पशुओं की रक्षा करने, पशुधन संसाधनों की हानि को रोकने और शमन करने के लिए 'आपदा प्रबंधन योजना' जारी की थी। विभाग ने एक 'पशुपालन कैलेंडर' भी जारी किया था जो किसानों के लिए एक माह-वार पशुपालन परामर्शी है जिसमें पशुधन पर उच्च तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने के लिए भी परामर्शी शामिल है। इसके अलावा, तेज गर्मी के महीनों के दौरान किसानों को उनके पशुओं का प्रबंधन करने के बारे में जागरूक करने के लिए एमकिसान पोर्टल के माध्यम से लघु संदेश सेवा (एमएमएस) भी भेजे जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार ने अप्रैल, 2016 में 'कार्य योजना की तैयारी-लू की रोकथाम और प्रबंधन' के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे जिसमें पशुधन पर उच्च तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए शमन योजना का विकास शामिल है। एनडीएमए ने सभी लू संभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लू पर परामर्श जारी की है जिसमें पशुओं की सुरक्षा करने का प्रावधान भी शामिल है। एनडीएमए लू से बचने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापनों और लघु टीवी वाणिज्यिक फिल्मों के माध्यम से समुदाय को संवेदनशील बनाने और जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान दे रहा है।
